(c) and (d) An outlay for Rs. 7215 crores has been approved in 9th Five year Plan and Rs. 726 crores in Annual Plan 1998-99 for development of major ports as per details given below:—

Sl. No.	Name of the Port	9th Plan Outlay (Rs. in Crores)	Outlay 1998-99 (Rs. in crores)
1.	Calcutta / Haldia	545	30.00
2.	Mimbai	980	110.00
3.	J L Nehru	500	70.50
4.	Chennai	1700	170.50
5.	Cochin	330	10.00
6.	Vizag	850	50.00
7.	Kandla	360	65.50
8.	Mormugao	260	15.00
9.	Paradip	900	120.00
10.	New Mangalore	340	30.00
11.	Tuticorin	450	55.00
	TOTAL	7215	726.00

लघु उद्योगों के लिए रियायतें

*239. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने लघु उद्योगों को विदेशी कम्पनियों के आगमन और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के आयात से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में लघु उद्योगों को कुछ प्रोत्साहन और रियायतें दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) देश में प्रारम्भ किए गए उदारीकरण और आर्थिक सुधारों को देखते हुए, लघु उद्योग (एस०एस०आई०) क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रतियोगी बने और स्वयं को उससे संबंधित चुनौतियों के लिए तैयार करें।

(ख) और (ग) प्राथमिकता क्षेत्र स्थिति, ऋण नीति पहल, उत्पाद-शुल्क रियायतें और उत्पाद आरक्षण कुछ ऐसे प्रोत्साहन हैं जो लघु उद्योग क्षेत्र को उसके विकास और वृद्धि के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Interest Rate on corpus of Provident Fund Pension

*240. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Standing Labour Committee recommended payment of 12 per cent interest on the corpus of provident fund pension of Rs. 13,000 crores;

(b) if so, why Government continue paying only 8½ per cent interest while even the States securities pay an interest of 13½ per cent and;

(c) whether Government would immediately raise the interest?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Over and above the 8½ per cent interest, the Government of India contributes to the Employess Pension Scheme at the rate of 1.16% of the pay of the employees. Under the circumstances, it has not been found feasible to raise the interest rate on the deposits in the public account.